

>

Title: Need to open sub-post offices in every village having population of 1000 or more in Satna Parliamentary Constituency, Madhya Pradesh.

श्री गणेश सिंह (सतना): सभापति महोदय, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामले की ओर भारत सरकार के डाक एवं संचार मंत्रालय का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ... (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: We have already started with the 'Zero Hour'. Nothing except what Shri Ganesh Singh is saying will go on record.

*(Interruptions)**

श्री गणेश सिंह : डाक एवं संचार मंत्रालय का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि देश के कई ऐसे बड़े गांव हैं, जहां पोस्ट आफिस नहीं हैं, जबकि केन्द्र एवं राज्य सरकारों ने कई जनकल्याणकारी योजनाएं पोस्ट आफिसों के माध्यम से हितग्राहियों के खाते खोलने एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन इत्यादि के भुगतान का काम करने की नीतियां बनायीं हुई हैं। रेलवे मंत्रालय ने रेल टिकट भी पोस्ट आफिस से देने की घोषणा की है। इसी तरह से मनरेगा में मजदूरों के भुगतान के खाते भी वहीं खोले गए हैं। लेकिन आज यह भी देखा जा रहा है कि देश के कई सुदूर अंचलों में 15-15 किलोमीटर तक कोई पोस्ट आफिस नहीं है। मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूँ कि मेरे लोक सभा क्षेत्र में कोटर एक ऐसी जगह है, जहां तहसील मुख्यालय है और आज तक वहां उप-डाकघर नहीं बना है। मैं भारत सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि देश में एक हजार की आबादी के उन सभी गांवों में उप-डाकघर खोले जाएं और केन्द्र और राज्य सरकारों ने जो योजनाएं चलायीं हैं, पोस्ट आफिस तक उन योजनाओं को लोगों तक ठीक ढंग से हम लोग चला सकें, इसलिए मैं भारत सरकार से मांग करता हूँ कि एक हजार की आबादी वाले सभी गांवों में पोस्ट आफिस खोले जाएं।
